

>

Title: Need to set up a monitoring mechanism to ensure payment of wages to labourers under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.

डॉ. चरण दास महन्त (कोरबा): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान अकुशल श्रमिकों को दी गई मजदूरी में 18155.20 करोड़ रुपये की मजदूरी में से मात्र 10339.72 करोड़ रुपये का संवितरण बैंकों एवं डाकघरों के माध्यम से की गई है जो कि मात्र 57 प्रतिशत राशि होती है। आगामी वर्ष हेतु लगभग 40,000 करोड़ राशि केन्द्र सरकार ने श्रमिकों के भुगतान हेतु निर्धारित किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 16-17 हजार करोड़ रुपये की राशि बिना बैंक के खातों एवं डाकघर के माध्यम से न होकर सीधे श्रमिकों को दिये जाने की व्यवस्था है। विगत चार वर्षों में अनेक शिकायतें मिली हैं कि सही हाथों में भुगतान नहीं पहुंच पा रहा है और अनेक राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में मनरेगा श्रमिकों के खाते बैंक एवं डाकघरों में नहीं खुल पा रहे हैं। श्रमिकों के मजदूरी भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा जांच हेतु कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है और न ही मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बैंक एवं डाकघर, केन्द्रीय शासन के अधीन संस्थायें हैं, ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिये सजग हो इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये जायें कि इस योजना में कार्य करने वाले मजदूरों के भुगतान में सतत निगरानी की विशेष व्यवस्था की जाये ताकि गरीब श्रमिकों को उनके पसीने की कमाई मिल सके।